27 OCT 11 2026.qxd 26-10-2026 22:53 Page 1



# रेल मंत्री एवं मुख्यमंत्रीने जयपुर 'खातीपुरा'-टाटा नगर-सांतरागाछी एक्सप्रेस ट्रेन को दिखायी हरी झंडी

**नयी रेल सेवासे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड एवं पश्चिम बंगालके बीच कनेक्टिविटी होगी मजबूत**

नई दिल्ली। जयपुर (खातीपुरा) - टाटानगर-सांतरागाछी एक्सप्रेस ट्रेन का सोमवार को शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव एवं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। केंद्रीय रेल मंत्री कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में दिलीप घोष, मंत्री, पश्चिम बंगाल सरकार, सुनील कोठारी, महापौर, विद्युत बरन महतो, सांसद एवं मंजू शर्मा, सांसद सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं नागरिक उपस्थित रहे। रेल मंत्री श्री वैष्णव ने कहा कि जयपुर को जमशेदपुर और कोलकाता से जोड़ने वाली नई ट्रेन सेवा




राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड तथा पश्चिम बंगाल के बीच रेल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगी। रेल मंत्री ने कहा कि नई सेवा से राजस्थान में रहने वाले प्रवासी श्रमिकों, व्यापारिक समुदायों, विद्यार्थियों और विभिन्न क्षेत्रों के बीच यात्रा करने वाले अन्य यात्रियों को लाभ होगा। झारखंड में रेलवे के विकास का उल्लेख करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि राज्य के लिए रेलवे बजट आवंटन ४५० करोड़ रुपये से बढ़कर ७,५०० करोड़ रुपये हो गया है, जो पहले के आवंटन का लगभग १६ गुना है।

राज्य में लगभग ७५,००० करोड़ रुपये की परियोजनाओं पर काम चल रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत झारखंड के ५७ स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है। इनमें गोड्डा, गोविंदपुर रोड, लोहरदगा, मधुपुर और मुरी सहित कई स्टेशनों पर कार्य पूरा हो चुका है। रेल मंत्री ने कहा कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देशभर में पुनर्विकास कार्य जारी हैं और १,३०० से अधिक स्टेशनों को विकास के लिए लिया गया है। पश्चिम बंगाल के कई स्टेशनों, जिनमें सांतरागाछी, जलपाईगुड़ी रोड, जयचंडी पहाड़, हल्दिया और कामाख्यागुड़ी शामिल हैं, का भी पुनर्विकास किया जा रहा है।श्री वैष्णव ने कहा कि रेलवे का विकास मध्यम वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की जरूरतों को ध्यान में रखकर किया जा रहा है, जिनके लिए रेलवे किफायती परिवहन का एक प्रमुख साधन है। उन्होंने जोर दिया कि स्टेशन पुनर्विकास और बेहतर कनेक्टिविटी से सभी आय वर्गों के यात्रियों को लाभ होगा।

## आईसीआईसीआई लाइफ गारंटीशुदा इंडेक्स्ड पेंशन प्लान लॉन्च

प्रयागराज -आईसीआईसीआई लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड ने आईसीआईसीआई लाइफ गारंटीशुदा इंडेक्स्ड पेंशन लॉन्च किया है। यह सेवानिवृत्ति आय से जुड़ा उत्पाद है, जो ग्राहकों को गारंटीशुदा एन्युटी और वेरिएबल एन्युटी का मिश्रण प्रदान करता है। इस सुविधा के तहत गारंटीशुदा आय वाला हिस्सा ग्राहकों को आय में स्थिरता प्रदान करता है, वहीं वेरिएबल वाला हिस्सा इंडेक्स से जुड़ी आय के जरिए उन्हें महंगाई से बचाने में मदद करता है। आईसीआईसीआई लाइफ इंश्योरेंस के मुख्य उत्पाद अधिकारी श्री विकास गुप्ता ने इस लॉन्च केसंबंध में अपनी टिप्पणी में कहा लोगों की जीवन प्रत्याशा बढ़ रही है, ऐसेमें उन्हें लंबी सेवानिवृत्ति अवधि के लिए योजना बनाने की ज़रूरत है। बढ़ते खर्चों और बदलती वित्तीय प्राथमिकताओं को देखते हुए, ऐसे सेवानिवृत्ति समाधान होना बहुत जरूरी है, जो स्थिरता भी प्रदानकरें और साथ ही बाज़ार से जुड़ी आय में वृद्धि की संभावना भी प्रदान करें। इस उत्पाद की मुख्य खूबी यह है कि इसमें ग्राहक 60 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक का हिस्सा गारंटीशुदा एन्युटी के रूप में चुन सकते हैं। शेष हिस्सा निफ्टी 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स से जुड़ा होता है, जिससे ग्राहक बाज़ार में भागीदारीकर अपने सेवानिवृत्ति के वृद्धावस्था में आय बढ़ने की संभावना का लाभ उठा सकते हैं।

## नई ओप्पो फाइंड एक्स10 सीरीज लॉन्च

प्रयागराज-ओप्पो इंडिया ने अपनी नई ओप्पो फाइंड एक्स10 सीरीज लॉन्च की है, जिसमें ओप्पो फाइंड एक्स10 और ओप्पो फाइंड एक्स10 प्रो मैक्स शामिल हैं। इसके साथ ही ओप्पो की इनोवेटिव और प्रीमियम फ्लैगशिप फाइंड एक्स सीरीज की 10वीं पीढ़ी की शुरुआत हो गई है। प्रीमियम स्मार्टफोन अनुभव का एक नया पैमाना तय करने के लिए तैयार की गई फाइंड एक्स10 सीरीज में शानदार टू-टू-लाइफ इमेजिंग, बेमिसाल परफॉर्मेंस, जबरदस्त बैटरी बैकअप और आकर्षक रिफाइंड डिजाइन का मेल है। इसके साथ ही, नया कलरओएस 17 यूजर्स को एक बेहतरीन और स्मूथ सॉफ्टवेयर अनुभव प्रदान करता है। ओप्पो ने अपने फ्लैगशिप कनेक्टेड इकोसिस्टम का विस्तार करते हुए ओप्पो एन्को एक्स4 और ओप्पो पैड मिनी भी पेश किए हैं, ताकि यूजर्स बिना किसी रुकावट के एक ही फ्लो में तस्वीरें ले सकें, कंटेंट बना सकें और शेयर कर सकें। कुल मिलाकर, यह पूरा फ्लैगशिप पोर्टफोलियो रोजमर्रा के अनुभव को और बेहतर बनाता है, जिससे हर एक शॉट, एडिट और शेयर बिल्कुल वास्तविक और उस पल के करीब महसूस होता है। लॉन्च के मौके पर ओप्पो इंडिया की कम्युनिकेशंस प्रमुख गोल्डी पटनायक ने कहा पिछली 10 पीढ़ियों से ओप्पो फाइंड एक्स सीरीज स्मार्टफोन इनोवेशन की सीमाओं को आगे बढ़ाती रही है।

## जेल में बंद कैदियों के मानवाधिकार पर मंथन

लखनऊ। प्रदेश की जेलों में बंद कैदियों के मानवाधिकार, स्वास्थ्य और सम्मानजनक जीवन को लेकर बड़ी बैठक हुई। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के विशेष प्रतिवेदक उपेन्द्र सिंह बघेल और महानिदेशक कारागार पी.सी. मीना के बीच कारागार प्रशासन को और अधिक संवेदनशील बनाने पर चर्चा हुई। बैठक में डीआईजी कारागार प्रदीप गुप्ता ने प्रेजेंटेशन के जरिए बताया कि यूपी की जेलों में बंदियों के स्वास्थ्य, कौशल विकास, मानसिक स्वास्थ्य, भोजन और अन्य बुनियादी सुविधाओं के लिए क्या-क्या कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि महिला बंदियों, उनके साथ रह रहे छोटे बच्चों, बुजुर्ग और दिव्यांग कैदियों की विशेष जरूरतों को ध्यान में रखकर अलग व्यवस्थाएं की जा रही हैं। जेलों को सिर्फ सजा की जगह नहीं, बल्कि सुधार और पुनर्वास का केंद्र बनाने पर जोर दिया जा रहा है।एनएचआरसी के विशेष प्रतिवेदक उपेन्द्र सिंह बघेल ने कहा कि जेल में बंद हर व्यक्ति के साथ गरिमा और मानवीय संवेदनशीलता के साथ पेश आना सबसे जरूरी है। उन्होंने यूपी की जेलों में बंदियों के साथ सम्मानजनक व्यवहार और सीसीटीवी के जरिए निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने के प्रयासों की सराहना की।बैठक में जेलों को अधिक सुरक्षित, मानवीय और सुधारोन्मुख बनाने पर विस्तार से मंथन हुआ। इस दौरान वरिष्ठ अधीक्षक कारागार रंग बहादुर पटेल समेत कई अधिकारी मौजूद रहे।

## यूपी बोर्ड : ७५२६ केंद्रो पर आयोजित होगी परीक्षा

लखनऊ (आससे.)। माध्यमिक शिक्षा परिषद की बोर्ड परीक्षा इस बार 7526 परीक्षा केंद्र पर आयोजित होगी।भगवती सिंह सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद ने जानकारी देते हुए बताया कि यूपी बोर्ड की परीक्षाओं के लिए परीक्षा केंद्र निर्धारण की कार्रवाई अंतिम तौर पर जारी कर दी गई है। प्रदेश के 862 राजकीय, 3276 ऐडेड इंटर कॉलेज तथा 3388 स्ववित्त पोषित विद्यालयों को यूपी बोर्ड परीक्षा के आयोजन के लिए प्रस्तावित किया गया है। चयनित परीक्षा केदो के आवंटन के संबंध में विद्यालय प्रबंधक, प्रधानाचार्य छात्र साक्ष्य सहित 28 अक्टूबर तक अपनी आपत्ति माध्यमिक शिक्षा परिषद में दर्ज कर सकते हैं। प्रदेश में सर्वाधिक परीक्षा केंद्र प्रयागराज में 269 बनाए गए हैं ।वहीं सबसे कम परीक्षा केंद्र जनपद महोबा में 29 निर्धारित किए गए हैं। भगवती सिंह सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद ने जानकारी देते हुए बताया की राजधानी लखनऊ में 127, उन्नाव में 122, रायबरेली में 108, कानपुर नगर में 116, कानपुर देहात में 73, प्रतापगढ़ में 164, चित्रकूट में 41, बांदा में 67, हमीरपुर में 40, ललितपुर में 50, झांसी में 65 तथा जालौन में 64 परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए हैं। चर्चित गाजीपुर जनपद में 187, जौनपुर में 181, भदोही में 81, मिर्जापुर में 104 तथा सोनभद्र में 66 परीक्षा केदो पर यूपी बोर्ड परीक्षा आयोजित की जाएगी।

# यूपी : अनलिमिटेड पोटेंशियल का स्टेट, प्रगति-गति से दे रहा जवाब-योगी

लखनऊ (आससे.)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश का मतलब पूछने वालों को अब प्रदेश की प्रगति और विकास की गति से जवाब मिल रहा है। उत्तर प्रदेश 'अनलिमिटेड पोटेंशियल' यानी असीमित संभावनाओं वाला प्रदेश है, जो निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर, तकनीक, उद्योग, रोजगार और नवाचार के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। एक समय निवेशक लखनऊ आने से इनकार कर देते थे, लेकिन नए उत्तर प्रदेश में ?50 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जिनमें ?15 लाख करोड़ की परियोजनाओं की ग्राउंड ब्रेकिंग हो चुकी है और साढ़े सात लाख करोड़ रुपये से अधिक के प्रस्ताव इसके लिए तैयार हैं। प्रदेश में 36 सेक्टोरल पॉलिसी हैं और सरकार का लक्ष्य उत्तर प्रदेश को जीसीसी, आधुनिक तकनीक और उच्च कौशल वाले रोजगार का प्रमुख केंद्र बनाना है।मुख्यमंत्री सोमवार को राजधानी में जीसीसी इनोवेशन समिट 2026 को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 10 वर्ष पहले लखनऊ में जीसीसी समिट की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। वर्ष 2015-16 में उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर समिट होना था, लेकिन एक भी इंडस्ट्री लीडर लखनऊ आने को तैयार नहीं हुआ। निवेशकों ने शहर की खतरनाक छवि का हवाला देकर आने से इनकार कर दिया। नतीजतन, उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए समिट दिल्ली के पांच सितारा होटल में आयोजित करना पड़ा। उस समय प्रदेश की पहचान उपद्रव, अराजकता, माफिया के वर्चस्व और पॉलिसी पैरालिसिस से थी।



जब व्यक्ति सुरक्षित नहीं था तो पूंजी कैसे सुरक्षित होती? इसी अकर्मण्यता और अव्यवस्था ने उत्तर प्रदेश को बीमारू बना दिया था। युवाओं के लिए नौकरी नहीं थी, व्यापारियों को सुरक्षा नहीं थी, सूर्यास्त के बाद महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल सकती थीं और बेटियां स्कूल नहीं जा सकती थीं। मुख्यमंत्री ने तत्कालीन सरकार के कुछ एमओयू पर टिप्पणी करते हुए कहा कि उन्हें देखकर लोग हंसेंगे। उस समय की सरकार को अंग्रेजी के 'ह्रस्व' और हिंदी के 'और' में भी अंतर नहीं महसूस होता था।मुख्यमंत्री ने बताया कि 2017 में सरकार बनने के बाद औद्योगिक विकास मंत्री और अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त इन्वेस्टर समिट की तैयारी को लेकर उनसे मिले। जब अधिकारियों ने समिट का नाम ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और निवेश लक्ष्य ?20 हजार करोड़ बताया तो उन्होंने पूछा कि लक्ष्य इतना कम है तो नाम ग्लोबल क्यों रखा है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि लखनऊ इन्वेस्टर समिट नाम रखिए या लक्ष्य को ग्लोबल स्तर का बनाइए। तब अधिकारियों ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कौन निवेश करेगा। मुख्यमंत्री ने उनसे पहले तैयारी करने, पॉलिसी व लैंड बैंक बनाने को कहा। उन्होंने लक्ष्य की निचली सीमा ?2 लाख करोड़ रखने का निर्देश दिया और रोड शो की तैयारी करने को कहा। पहले इन्वेस्टर समिट में ?4.65 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले। आज प्रदेश में ?50 लाख करोड़ से अधिक के प्रस्ताव हैं, ?15 लाख करोड़ की ग्राउंड ब्रेकिंग हो चुकी है और साढ़े सात लाख करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाएं तैयार हैं।

**जामुन तोड़ने पर खूनी हमलावरकी अपील खारिज**
(विधि संवाददाता)

प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जामुन तोड़ने को लेकर हुए जानलेवा हमले के आरोपी को कोई राहत देने से इन्कार कर दिया। कोर्ट ने कहा चोट मेडिकल रिपोर्ट से मेल खाती है, प्रथम दृष्टया केस बनता है, ट्रायल कोर्ट ने सही सम्मन किया है।और अपील खारिज कर दी।

यामीन उर्फ मोमिन की याचिका पर न्यायमूर्ति संतोष राय ने यह आदेश पारित किया।थाना धौलाना, जिला हापुड़ में एस सी एस टी एक्ट केस में स्पेशल जज हापुड़ के संज्ञान-सम्मन आदेश को चुनौती दी गई थी।आरोपी यामीन उर्फ मोमिन और २ अज्ञात पर आरोप है कि सूचनाकर्ता के बेटे श्रीराम उर्फ ओम के जामुन तोड़ने के दौरान आरोपी ने हमला कर घायल कर दिया। बेटे को गंभीर चोटें आईं। सूचना पर पिता मौके पर पहुंचे। कोर्ट ने कहा ट्रायल कोर्ट को इस स्टेज पर सबूतों की बारीकी से जांच नहीं करनी है, सिर्फ देखना है कि प्रथम दृष्टया केस बनता है या नहीं। अपीलार्थी की दलील थी कि उसे झूठा फंसाया गया है, कोई आधार नहीं है।

# विपक्ष के झूठे और दोहरे मानदण्ड को जनता के बीच उजागर करेगी भाजपा-धर्मपाल सिंह

लखनऊ (आससे.)। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र बचाओ-अराजकता हटाओ अभियान चलाकर संवैधानिक मूल्यों तथा चुनावी प्रक्रियों के संबंध में विपक्ष के झूठे राजनैतिक एजेंडे और दोहरे मानदण्ड को जनता के बीच पहुंचकर उजागर करेगी। प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह ने सोमवार को प्रदेश भाजपा मुख्यालय में अभियान की प्रदेश टोली की बैठक का मार्गदर्शन करते हुए कहा कि भाजपा लोकतंत्र बचाओ-अराजकता हटाओ अभियान के द्वारा विपक्ष के आधारहीन विरोध प्रदर्शनों का उत्तर देगी।प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह ने कहा कि भाजपा 6 क्षेत्रों में पदयात्राएं निकालेगी। पदयात्राओं के माध्यम से विपक्ष की देश विरोधी राजनीति, सत्ता परिवर्तन के खतरनाक एजेंडे, देश को अस्थिर करने के खतरनाक मंसूबों को जनता के समक्ष प्रस्तुत करेगी और राष्ट्रीय एकता, संवैधानिक मूल्यों, सामाजिक समरसता, नागरिक कर्तव्यों के माध्यम से जनता को एकजुट करेगी। भाजपा पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, मोर्चा-प्रकोष्ठ पदाधिकारी, संत, महात्मा, व्यापारी, शिक्षक, अधिवक्ता, चिकित्सक, विभिन्न सामाजिक एवं धार्मिक संगठन, भाजपा कार्यकर्ता एवं स्थानीय नागरिक लोकतंत्र की हुंकार और अराजकता की हार के संकल्प के साथ पदयात्रा पर निकालेगें। अवध क्षेत्र की पदयात्रा 3 नवम्बर को लखनऊ में निकलेगी। काशी क्षेत्र की पदयात्रा प्रयागराज में 4 नवम्बर तथा गोरखपुर क्षेत्र की पदयात्रा गोरखपुर में 4 नवम्बर को निकलेगी। कानपुर-बुन्देलखण्ड क्षेत्र की पदयात्रा कानपुर में 4 नवम्बर को तथा पश्चिम क्षेत्र की गाजियाबाद और बृज क्षेत्र की पदयात्रा बरेली में 5 नवम्बर को निकलेगी।बैठक में प्रदेश महामंत्री एवं अभियान के संयोजक दिलीप पटेल ने अभियान की तैयारियों की विस्तृत चर्चा की। बैठक में अभियान टोली के सह संयोजक प्रदेश उपाध्यक्ष प्रियंका सिंह रावत, नीरज सिंह, प्रदेश मंत्री अंकुर शर्मा, पदयात्रा प्रमुख एवं प्रदेश महामंत्री संजय राय सहित प्रदेश उपाध्यक्ष देवेश कोरी, रमेश सिंह, प्रदेश महामंत्री राम प्रताप सिंह चौहान, गीता शाक्य, अभिजात मिश्रा, प्रदेश मंत्री अवधेश श्रीवास्तव, महामेधा नागर, दीपमाला संतोषी, प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा रोहित मिश्रा, प्रदेश मीडिया संयोजक मनीष दीक्षित, सह संयोजक हिमांशु दुबे, प्रदेश सोशल मीडिया संयोजक हिमांशु राज पंडित, क्षेत्रीय अध्यक्ष पूरन लाल लोधी, अवधेश द्विवेदी, अशोक चौरसिया, विनोद राय एवं राम किशोर साहू उपस्थित रहे।

# चक्रवात 'अर्णब' को लेकर यूपी में अलर्ट राहत-बचाव की तैयारियों में जुटी योगी सरकार

लखनऊ (आससे.)। चक्रवात 'अर्णब' के संभावित प्रभाव से उत्तर प्रदेश में 28 से 31 अक्टूबर के बीच बेमौसम बारिश, गरज-चमक और तेज हवाएं चलने की आशंका है। इसको देखते हुए योगी सरकार अलर्ट हो गई है। मौसम पूर्वानुमान को देखते हुए उत्तर प्रदेश राहत आयुक्त

## यूपी में २८ से ३१ अक्टूबर तक बारिश और तेज हवाओं का पूर्वानुमान

कार्यालय ने जनसामान्य और किसानों के लिए सतर्कता संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए हैं। प्रदेश सरकार ने संभावित मौसम परिवर्तन के मद्देनजर राहत-बचाव और एहतियाती उपायों पर जोर दिया है। मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक 28 अक्टूबर को सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, भदोही, गाजीपुर और बलिया में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 29 अक्टूबर को कई जिलों में भारी बारिश और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की आशंका के चलते ऑरेंज अलर्ट है। चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, रायबरेली, अमेठी और सुल्तानपुर सहित कई क्षेत्रों में वर्षा का अनुमान है। 30 अक्टूबर को पूर्वांचल, अवध और तराई के कई जिलों के साथ बरेली, पीलीभीत और शाहजहांपुर में भी भारी बारिश व तेज हवाओं की संभावना जताई गई है। इसके चलते दिन के तापमान में 5 से 8 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ सकती है।राहत आयुक्त कार्यालय ने लोगों से मौसम संबंधी चेतावनियों और प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। आंधी-तूफान के दौरान पक्के भवनों में शरण लेने, पेड़ों, बिजली के खंभों और कमजोर संरचनाओं से दूर रहने व अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। बिजली कड़कने के दौरान खुले मैदानों, खेतों और जलाशयों के पास जाने से भी बचने को कहा है।

# अयोध्या, काशी-मथुरा की तर्ज पर होगा संकिसा, बौद्ध सर्किट का समग्र एवं सुनियोजित विकास- केशव प्रसाद मौर्य

मैनपुरी/ फर्रुखाबाद (एजेंसी)। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जसराजपुर संकिसा में आयोजित अभिधम्म दिवस महोत्सव को संबोधित करते हुए कहा कि संपूर्ण मानवता को करुणा, दया, अहिंसा और शांति का अमर संदेश देने वाले तथागत भगवान बुद्ध केवल भारत ही नहीं बल्कि समूचे विश्व में आराध्य एवं वंदनीय हैं। उन्होंने कहा कि भारत भूमि पर भगवान बुद्ध से जुड़े आठ प्रमुख पावन तीर्थ स्थलों में संकिसा का एक अत्यंत विशिष्ट, ऐतिहासिक और गौरवशाली स्थान है। उन्होंने इस पावन धरा, यहां के निवासियों को सादर नमन करते हुए देश-विदेश से पधारे



सभी पूज्य भंतेगणों, उपासकों और बुद्ध अनुयायियों का हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन किया। उन्होंने संकिसा में पाली शोध संस्थान एवं विपश्यना ध्यान केंद्र की स्थापना की मांग पर स्पष्ट करते हुए कहा कि यह जनता के लिए कोई मांग का विषय नहीं बल्कि उनका स्वाभाविक अधिकार है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि मैनपुरी और फर्रुखाबाद दोनों जनपदों के समन्वय से संकीसा के समग्र विकास के लिए एक सुनियोजित एवं विस्तृत कार्य-योजना तैयार की जायेगी।अभिधम्म दिवस के पावन अवसर पर जनपद फर्रुखाबाद स्थित ऐतिहासिक बौद्ध तीर्थस्थली संकिसा में पवित्र बौद्ध स्तूप के दर्शन-पूजन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरणा लेकर समाज में शांति, करुणा एवं परस्पर सम्मान की भावना निरंतर मजबूत हो, यही मंगलकामना है।उन्होंने कहा कि इस पावन स्थल के विकास के लिए जनता ने जितनी अपेक्षाएं रखी हैं, सरकार उन अपेक्षाओं से कहीं आगे बढ़कर कार्य धरातल पर उतारने का प्रयास करेगी ताकि संकीसा की वैश्विक पहचान और अधिक सुदृढ़ हो सके। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्तमान समय में तथागत भगवान बुद्ध के सबसे बड़े अनुयायी के रूप में कार्य कर रहे हैं, उन्होंने यह सिद्ध करके दिखाया है।

# इलाहाबाद हाईकोर्टने शादी रजिस्ट्रेशनको लेकर जारीकी गाइडलाइन

**कहा-आधारसे नहीं साबित होगी उम्र, सिर्फ टीसी पर भी नहीं होगा शादी रजिस्ट्रेशन**

(विधि संवाददाता)

प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विवाह पंजीकरण की प्रक्रिया में गंभीर कमियां मिलने पर राज्य सरकार और पंजीकरण विभाग को कड़े निर्देश जारी किए हैं। अदालत ने स्पष्ट कहा है कि आधार कार्ड केवल किसी व्यक्ति की पहचान साबित करता है, लेकिन उसे जन्मतिथि या उम्र का प्रमाण नहीं माना जा सकता। इसी तरह केवल ट्रांसफर सर्टिफिकेट (टीसी) के आधार पर भी शादी का रजिस्ट्रेशन नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने इस पूरे मुद्दे को बाल विवाह रोकने की आवश्यकता से जोड़ते हुए व्यवस्था में सुधार की जरूरत बताई ।यह आदेश न्यायमूर्ति तेज प्रताप तिवारी ने दीपक पाल की अपील पर सुनवाई करते हुए पारित किया। मामले की पड़ताल के दौरान अदालत के सामने यह तथ्य आया कि संबंधित विवाह का पंजीकरण आधार कार्ड और ट्रांसफर सर्टिफिकेट के आधार पर किया गया था। अदालत ने पाया कि उम्र के सत्यापन को लेकर आवश्यक सावधानी नहीं बरती गई।हाईकोर्ट ने कहा कि आधार कार्ड को जन्मतिथि का वैध प्रमाण नहीं माना जा सकता। वहीं ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी किशोर न्याय अधिनियम की धारा ९४ में बताए गए दस्तावेजों की श्रेणी में शामिल नहीं है। अदालत ने यह भी कहा कि जिस ट्रांसफर सर्टिफिकेट के आधार पर विवाह पंजीकरण किया गया, उसका निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सत्यापन भी नहीं कराया गया था। ऐसी स्थिति में पंजीकरण अधिकारी के पास आयु संबंधी कोई प्रमाणित दस्तावेज उपलब्ध नहीं था और उसने अपनी कानूनी जिम्मेदारी सही ढंग से नहीं निभाई।

अदालत ने कहा कि जब तक उत्तर प्रदेश विवाह पंजीकरण नियमावली-२०१७ में आवश्यक संशोधन नहीं किए जाते, तब तक कुछ विशेष दिशानिर्देशों का पालन किया जाए। कोर्ट ने सबसे पहले यह सुनिश्चित करने को कहा कि लड़के की न्यूनतम आयु २१ वर्ष और लड़की की १८ वर्ष से कम होने पर किसी भी विवाह का पंजीकरण न किया जाए।अदालत ने निर्देश दिया कि यदि उपलब्ध दस्तावेजों या अन्य सामग्री से किसी पक्ष की उम्र कम होने का तार्किक संदेह पैदा होता है तो विवाह का पंजीकरण सामान्य प्रक्रिया में न किया जाए। ऐसे मामलों की सूचना तुरंत विवाह प्रोबेशन अधिकारी और जिलाधिकारी को भेजी जाए ताकि कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई हो सके।कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि ऑनलाइन व्यवस्था ऐसी बनाई जाए जिसमें केवल आधार ऑथेंटिकेशन के आधार पर विवाह प्रमाणपत्र जारी न हो सके। दोनों पक्षों की जन्मतिथि का सत्यापन अनिवार्य रूप से रिकॉर्ड किया जाए और उसके स्रोत का भी उल्लेख हो। यदि सत्यापन अधूरा हो या किसी प्रकार की त्रुटि सामने आए तो आवेदन स्वत: आगे न बढ़ सके।अदालत ने राज्य सरकार से उम्र संबंधी प्रमाणों के बारे में स्पष्ट मानक तय कर व्यापक स्तर पर प्रसारित करने को कहा है। कोर्ट ने धारा ९४ के अनुरूप जन्म प्रमाणपत्र और हाईस्कूल के शैक्षणिक रिकार्ड को प्रमुख दस्तावेजों के रूप में रेखांकित किया।प्रिंसिपल सेक्रेटरी, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन को पोर्टल पर सत्यापन का पूरा विवरण दर्ज करने, अनियमितताओं को फ्लैग करने और अधूरे सत्यापन वाले मामलों में प्रमाणपत्र जारी होने से रोकने के निर्देश दिए गए हैं। रजिस्ट्रार जनरल को आदेश की प्रति सभी जिला जजों तक पहुंचानी होगी। जिला जज, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में जिलाधिकारी, पंजीकरण अधिकारियों, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अधिकारियों तथा बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। साथ ही इस विषय को जिला मॉनिटरिंग सेल की बैठकों में भी रखा जाएगा।कोर्ट ने आईजी रजिस्ट्रेशन, उत्तर प्रदेश को विवाह पंजीकरण अधिकारियों के लिए राज्यस्तरीय जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने का निर्देश दिया है। इसके लिए लखनऊ स्थित न्यायिक प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान के निदेशक से समन्वय कर विशेषज्ञ उपलब्ध कराए जाएंगे। रजिस्ट्रेशन विभाग को समय-समय पर निरीक्षण कर रिकॉर्ड सुरक्षित रखने को कहा गया है। वहीं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव प्रत्येक दो महीने में पंजीकरण कार्यालयों का निरीक्षण करेंगे, हाल में दर्ज विवाहों के नमूने और आयु सत्यापन रिकॉर्ड की जांच करेंगे तथा रिपोर्ट जिला जज को भेजेंगे। मामले की अगली सुनवाई २७ नवंबर २०२६ को होगी और तब तक अदालत ने अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

# पृष्ठ एक का शेष

**सपा-कांग्रेस...**

साधा। सीएम योगी ने कहा, भगवान राम पुष्पक विमान से लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद अयोध्या आए। हजारों वर्षों पहले भगवान राम आए थे। हजारों वर्षों तक अयोध्या में आवागमन के लिए केवल सड़क मार्ग था वह भी टूटा-फूटा था। बिजली गायब थी। सब कुछ गायब। गंदगी रहती थी। जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के संस्कार हैं गंदगी में रहने की आदत, गंदे कार्यों को करने आदत अंधेरे में डकैती डालने की जो आदत थी वही उन्होंने अयोध्या में भी किया। अयोध्या को बिजली नहीं दी। अयोध्या का विकास नहीं किया और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अयोध्या के विकास के लिए कार्य योजना बनाई तो उन्होंने रोड़े अटकाने शुरू किए। सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में काशी में काशी विश्वनाथ धाम, जहां 17 के पहले 20 श्रद्धालु एक साथ दर्शन नहीं कर सकते थे, आज उसी काशी विश्वनाथ धाम में 20,000 श्रद्धालु एक साथ दर्शन की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। चमक गई है काशी। नए कलेवर के रूप में नई काशी आ चुकी है। प्रधानमंत्री जी ने उसकी कायाकल्प कर दी है। और अयोध्या फिर से चमक पड़ा है।

**मोदीके पिता...**

अब बीजेपी ने इसे मुद्दा बना लिया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के खिलाफ पटना बीजेपी का विरोध प्रदर्शन एवं पुतला दहन कार्यक्रम शुरू। बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता पार्टी दफ्तर से निकले। इनकम टैक्स चौराहे तक विरोध प्रदर्शन किये। बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस अध्यक्ष खरगे से बिना शर्त माफी मांगने की मांग की है। बीजेपी का कहना है कि राजनीतिक मतभेदों को व्यक्तिगत अपमान का रूप नहीं देना चाहिए। आज देशभर में बीजेपी कार्यकर्ता कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं। बीजेपी आज हर जिला मुख्यालय पर प्रोटेस्ट कर रही है। पटना में बीजेपी प्रदेश कार्यालय से आयकर गोलंबर तक विरोध मार्च निकाल रही है और पुतला दहन करेगी। बीजेपी ने कहा कि खरगे ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो पहले गुंडों और बदमाशों से जुड़ी मानी जाती थी। पार्टी ने इसे कांग्रेस की 'वैचारिक दिवालियापन' का संकेत बताते हुए कहा कि कांग्रेस अब राजनीतिक दल के बजाय %माफिया गैंग% जैसी दिखने लगी है।

**ब्रिक्स...**

और जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक चुनौतियों के बीच संवाद, कूटनीति और सहयोग का महत्व बढ़ गया है। संसदें आपसी विश्वास मजबूत करने और समस्याओं के शांतिपूर्ण समाधान में प्रभावी योगदान दे सकती हैं। साथ ही, वैश्विक दक्षिण की आकांक्षाओं को ठोस नीतियों और व्यावहारिक सहयोग में बदलना आवश्यक है।इस वर्ष संसदीय मंच का विषय 'जन-केंद्रित विकास के लिए संसदों को सशक्त बनाना' है। दो दिवसीय बैठक में लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास पर चर्चा होगी। बिरला ने कहा कि विकास और पर्यावरण एक-दूसरे के पूरक हैं। उन्होंने संसदों से युवाओं की आकांक्षाओं को समझने, उन्हें बेहतर अवसर देने और उनकी प्रतिभा को राष्ट्र निर्माण से जोड़ने का भी आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी के ब्रिक्स को 'समाधानों का पारिस्थितिकी तंत्र' बनाने के विचार का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि सदस्य देशों को साझा उद्देश्यों के लिए विश्वास और सहयोग बढ़ाना चाहि